

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-04

देहरादून दिनांक २। सितम्बर, 2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति (शत प्रतिशत के 0पो0) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि के वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1062/XVII-4/2015-10(43)/2014 दिनांक 23.08.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कुल ₹73.01 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि ₹73.01 करोड़ में से शासनादेश सं0-1115/XVII-4/2015-10(43)/2014 दिनांक 05.09.2016 द्वारा ₹20.62 करोड़ वित्तीय वर्ष 2014-15 के छात्र-छात्राओं हेतु आवंटित करने के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹52.39 करोड़ वित्तीय वर्ष 2015-16 के छात्र-छात्राओं हेतु आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें तथा अब उक्त मद में भारत सरकार से कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हो पा रही है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार से प्राप्त उक्त धनराशि (₹52.39 करोड़) वर्ष 2015-16 की देयता के आधार पर ही शासनादेश सं0-629/XVII-4/2015-01(10)/2015 दिनांक 26.03.2015 में निर्धारित प्रक्रिया यथा- जिन-जिन शिक्षण संस्थाओं की छात्रवृत्ति की जांच जिलाधिकारी द्वारा की जा चुकी है तथा जांच आख्या में कोई आपत्तिजनक तथ्य इंगित नहीं हैं, अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कुल देय धनराशि का 50 प्रतिशत उन छात्रों को जिनके आवेदन पत्र पहले प्राप्त हुए हैं, को सुनिश्चित करते हुए अवरोही क्रम में प्राथमिकता के आधार पर धनराशि का ऑनलाईन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या-1164(1)/XVII-4/2015-10(43)/2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. आदेश पंजिका।

आज्ञा से
(राजेन्द्र कुमार मट्ट)
उप सचिव।